

‘इण्डो- यूएस ट्रेड डील पर चार-पांच दिन में दोनों देश संयुक्त बयान देंगे’

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि संयुक्त वक्तव्य के बाद वाइट हाउस के एग्जीक्युटिव आदेश से यूएस टैरिफ घटकर 18 प्रतिशत रह जाएगा

-डॉ. सतीश मिश्रा-

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 05 फरवरी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि अमेरिका-भारत व्यापार समझौते का पहला चरण लगभग तैयार है और दोनों देश चार-पांच दिनों में संयुक्त बयान जारी करेंगे। सोमवार रात अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प द्वारा दृढ़ सोशल पर की गई घोषणा के बाद दिल्ली और वाशिंगटन के बीच समझौते की पहली जानकारी सामने आने लगी है।

गोयल ने कहा कि संयुक्त बयान के बाद वाइट हाउस के कार्यकारी आदेश के जरिए अमेरिकी टैरिफ 18 प्रतिशत तक कम हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर करने में 30-45 दिन लगेगे और इसे मार्च में साइन किया जाएगा।

- पीयूष गोयल ने बताया कि औपचारिक एग्रीमेंट होने में 30 से 45 दिन लगेगे और संभवतया मार्च तक एग्रीमेंट हो जाएगा और इस पर मार्च में वर्चुअली साइन किये जाएंगे।
- ट्रंप ने ट्रेड डील की घोषणा सोमवार रात की थी जिसमें यह भी कहा था कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा। इसे स्पष्ट करते हुए वाणिज्य विभाग के अफसरों ने बताया कि विमान खरीद के ही ऑर्डर 70-80 अरब डॉलर के होंगे। भारत ईंधन, विमान व चिप्स खरीद पर 300 अरब डॉलर खर्च करेगा।
- वेनेजुएला से ईंधन खरीदने के ट्रंप के दावे पर विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, वेनेजुएला हमारा पुराना सहयोगी है, हम उससे तेल खरीदते रहे हैं। पर प्रवक्ता ने रुस से तेल खरीद के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा।

उन्होंने बताया कि संयुक्त समझौते पर वर्चुअल तरीके से हस्ताक्षर किए जाएंगे और संयुक्त बयान के बाद कार्यकारी आदेश के जरिए भारत से आने वाले सामान पर अमेरिकी शुल्क 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

गोयल ने कहा, “हम चाहते हैं कि समझौता जल्दी हो, क्योंकि इसके बाद हमें और रियायतें मिल सकती हैं।”

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा, “मार्च में लीगल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत अमेरिका के सामान पर शुल्क कम करेगा।”

ट्रम्प के इस दावे पर भी कुछ स्पष्टता सामने आई कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा।

व्यापार अधिकारियों ने बताया कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

व्हीलचेयर पर संसद पहुंचे थरुर

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 5 फरवरी। संसद के मकर द्वार से व्हीलचेयर से गुजरते हुए, शशि थरुर ने कहा कि वह संसद में अपने कर्तव्यों और केरल में अपने चुनावी कार्य को जारी रखेंगे। ज्ञातव्य है कि बुधवार को थरुर संसद भवन में गिर गए इस कारण उनके पैर में एक हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया है।

पत्रकारों से बात करते हुए, तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस के सांसद थरुर ने कहा कि उनका पैर कास्ट में रहेगा और ठीक होने में कम से कम 4-6 सप्ताह लगेगे। थरुर ने कहा, “मैं

- कांग्रेस के सांसद शशि थरुर बुधवार को संसद की सीढ़ियों से लड़खड़ाकर गिर गए थे, उनके पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर है।

अपना काम जारी रखूंगा, लेकिन मुझे व्हीलचेयर का उपयोग करना होगा, कम से कम इस (बजट) सत्र के इस भाग में शामिल होने के लिये।” बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होने वाला है।

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें बुरी नजर लग गई है, तो थरुर ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, “लगे रहने दो (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प.बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस

खड़गे के आवास पर गुरुवार को हुई प्रदेश कांग्रेस की बैठक में हुआ बड़ा फैसला

—श्रीनंद झा—

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 5 फरवरी। गठबंधन राजनीति में शामिल रहने के लगभग डेढ़ दशक के बाद, कांग्रेस ने आगामी पश्चिम बंगाल चुनावों में अकेले उतरने का फैसला किया है।

1970 के दशक तक प.बंगाल पर कांग्रेस का प्रभुत्व था पर बाद में धीरे-धीरे कांग्रेस कमजोर होती गई और उसकी खाली जगह पर पहले वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। गठबंधन राजनीति से जुड़ने से कांग्रेस को कोई खास लाभ नहीं हुआ। वर्ष 2011 में, कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और 42 सीटें जीतीं। वर्ष 2016 में, पार्टी ने माकपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा और 44 सीटें जीतीं। पिछले 2021 के चुनावों में, कांग्रेस ने फिर से माकपा नेतृत्व वाले वाम मोर्चे के साथ गठबंधन किया, लेकिन अपना खाता भी नहीं खोल सकी।

पार्टी के राज्य नेतृत्व की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नई दिल्ली स्थित निवास, 10 राजाजी मार्ग पर गुरुवार को हुई बैठक के बाद “एकला चालो” निर्णय लिया गया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद थे।

बैठक में राज्य के नेताओं ने पार्टी नेतृत्व को बताया कि वाम मोर्चे के साथ गठबंधन से अब खास सफलता नहीं मिल रही है। क्योंकि वाम नेताओं ने कांग्रेस से “संसाधन तो खींचे, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में वोट ट्रांसफर करने में सक्षम नहीं हो सके”। उन्होंने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के साथ चुनावी समझौते को भी नकारात्मक रूप से देखा, क्योंकि

- डेढ़ दशक तक कभी वाम मोर्चा तो कभी तृणमूल के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस का मन लगता है अब भर चुका है।

- गत चुनाव कांग्रेस ने वाम मोर्चा के साथ लड़ा था पर पार्टी का खाता भी नहीं खुला ,इसलिए इस बार वाममोर्चा के साथ कांग्रेस गठबंधन नहीं करना चाहती और तृणमूल पार्टी का रवैया बेहद घमंडी है इसलिए कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी।

- सत्तर के दशक तक बंगाल की राजनीति में कांग्रेस का दबदबा था, धीरे-धीरे पार्टी कमजोर होती गई तो पहले वाम मोर्चा और फिर तृणमूल ने कांग्रेस की छोड़ी हुई जगह हथिया ली।

तृणमूल कांग्रेस का रुख काफी “घमंडी और अक्खड़” था। पिछले विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस से गठबंधन नहीं कर पाई, क्योंकि तृणमूल ने कांग्रेस को “बेहद कम” सीटों पर प्रस्ताव दिया था। राज्य के नेताओं ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का यह मत था कि कांग्रेस सिदेबाजी करने की स्थिति में भी नहीं थी। ममता बनर्जी के भतीजे और वरिष्ठ तृणमूल नेता ने यहां तक कि सुझाव दिया था कि कांग्रेस को तृणमूल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिहार चुनाव में “कैश ट्रांसफर” के मुद्दे पर आज सुनवाई संभव

चुनाव आचार संहिता के दौरान, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को दस हजार रु. देने के खिलाफ प्रशांत किशोर ने याचिका दायर की है

- जाल खंबाता -

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 5 फरवरी। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित जन सुराज पार्टी ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सरकार की कल्याण योजना के दुरुपयोग के आरोप में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वह विधानसभा चुनाव रद्द कराने की मांग कर रहे हैं।

किशोर की पार्टी ने 2025 के चुनावों में 243 विधानसभा सीटों में से 242 पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट जीतने में असफल रही। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का मुख्य मुद्दा बिहार सरकार द्वारा चुनावों से ठीक पहले शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने हर परिवार की

- इस योजना के तहत सभी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए दस-दस हजार रु. दिए गए थे और वादा किया गया था कि आकलन के बाद काम संतोषप्रद रहा तो 2 लाख रु. और दिए जाएंगे।

- प्रशांत किशोर ने याचिका में आरोप लगाया है कि यह योजना विधानसभा की मंजूरी के बिना मंत्रिमंडलीय फैसले के आधार पर लागू कर दी गई थी और इसके लिए सरकार के आकस्मिक कोष से फंड जुटाया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 267 का उल्लंघन था।

- उन्होंने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू था तब 1.56 करोड़ महिलाओं के खातों में दस-दस हजार रु. दिए गए थे, यह “भ्रष्ट आचरण” है।

एक महिला को 10,000 रु. सीधे देने का निर्णय लिया था, ताकि वह स्व-रोजगार शुरू कर सके, साथ ही एक और वादा किया गया 2 लाख रु. का, जो

व्यवसाय का आकलन के बाद दिया जाएगा।

याचिका के अनुसार, इस योजना (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईसाई रीति से हुए विवाहों का रजिस्ट्रेशन करें- हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि ईसाई विवाह अधिनियम के तहत जारी विवाह प्रमाण पत्रों को सिविल रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार नहीं किया जा सकता। यह राज्य का वैधानिक दायित्व है और इसे किसी अधिकारी के विवेकाधीन निर्णय के

- विवाह पंजीकरण नहीं होने से ईसाई दंपतियों को पासपोर्ट, वीजा सहित अन्य सरकारी सेवाओं के लिये कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अधीन नहीं रखा जा सकता। जस्टिस पीएस भाटी और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश सिरो-मालाबार रोमन कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट ईचार्ज फादर पॉल पी की ओर से दायर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चुनावों में बढ़ते “रेवड़ी कल्चर” पर सुप्रीम कोर्ट का रुख गंभीर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस विषय पर गंभीर चिंतन की जरूरत है इसलिए इस पर तीन सदस्यीय बेंच विचार करेगी

- जाल खंबाता -

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 5 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि चुनावी घोषणापत्र और चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त योजनाओं के वादे करने का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। यह सार्वजनिक हित से जुड़े गंभीर सवाल उठाता है और इस पर तीन जजों की बेंच को विचार करना चाहिए।

यह टिप्पणी उस समय की गई जब भाजपा नेता और वकील याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने चुनावी घोषणापत्र और प्रचार के दौरान मुफ्त योजनाओं की घोषणा पर रोक लगाने की मांग की है।

यह संकेत देते हुए कि मामला बड़ी बेंच के सामने रखा जाएगा, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण

- मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय से कहा, यह जनहित का गंभीर मुद्दा है और इसे तीन सदस्यीय बेंच द्वारा सुना जाना चाहिए। इसे मार्च में सुना जाएगा तब तक इंतजार कीजिए।

- याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में चुनावों में मुफ्त सामान बांटने के “रेवड़ी कल्चर” पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि 5 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अब सिर्फ सूरज, चांद देने का वायदा किया जाना ही बचा है।

- राजनैतिक दलों ने इस याचिका का विरोध किया तथा इसे राजनैतिक रूप से प्रेरित बताया। उनका कहना है कि लोक कल्याणकारी योजनाएं व सब्सिडी शासन का अस्म भाग हैं इसका लक्ष्य कमजोर तबकों की मदद करना होता है।

- सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में भी सुनवाई के दौरान मुद्दे को जटिल बताया था और अपनी न्यायिक सीमाओं की मजबूरी का उल्लेख किया था।

और सार्वजनिक हित का मामला है...

इसे तीन जजों की बेंच को सुनना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस महीने के बाद मामले की सुनवाई होगी। उन्होंने कहा, “मार्च तक

इंतजार करें।”

उपाध्याय ने अदालत से मामले की तुरंत सुनवाई करने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि आने वाले महीनों में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले

हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल वोटरों को प्रभावित करने के लिए लगातार वादे कर रहे हैं, जो उनके अनुसार भ्रष्ट आचरण है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गुरुवार को ठप्प रही लोकसभा

नयी दिल्ली, 05 फरवरी। लोकसभा में गुरुवार को भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

तीन बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर तीन बजे शुरू होते ही विपक्षी सदस्य फिर से नारेबाजी करने

- लोकसभाध्यक्ष ने दिन भर के लिए कार्यवाही स्थगित करते हुए कहा सदस्य पोस्टर लेकर आएं तो सदन नहीं चलेगा।

लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामे के बीच कहा कि बड़े दुख के साथ सभा को सूचित करना है कि कल कुछ सदस्यों ने जिस प्रकार का व्यवहार किया और ऐसे दृश्यों का सुजन किया, वह लोकसभा के शुरुआत से लेकर आज तक आज तक कभी नहीं हुआ। संसदीय प्रणाली में सदन के समापति का परिणामय स्थान हमारे संविधान में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दावे ही बाकी रह गए हैं। यह अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अपनी उपलब्धि दिखाने के लिए जोर-शोर से किया गया दावा है। ट्रम्प ने भारत से बहुत बड़ी मांग की थी। वह चाहते थे कि भारत में आने वाले अमेरिकी सामान पर सभी टैरिफ हटा दिए जाएं, जबकि अमेरिका भारतीय उत्पादों पर अपने शुल्क बनाए रखे। सही नहीं कहा जा सकता।

भारत की ओर से इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि अमेरिकी सामान भारत में बिना शुल्क के आएगा। इसके बजाय कुछ बातों से संकेत मिले हैं कि तय कार्यक्रम के अनुसार भारत में आने वाले सामान पर चरणबद्ध तरीके से शुल्क लगाए जाएंगे।

यह संभव नहीं है कि भारत सभी अमेरिकी आयात पर छूट दे, जबकि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- हालांकि, ट्रेड डील को लेकर अभी सिर्फ कयास ही लग रहे हैं लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अमेरिका की दबाव डालने की रणनीति भारत पर कारगर नहीं हुई और यूरोपियन यूनियन के साथ हुई ट्रेड डील से तो अमेरिका की हताशा और बढ़ गई।

- यही वजह रही कि कभी भारत को “डैड इकॉनमी” बताने वाले ट्रंप ने खुद ही ट्रेड डील स्वीकृत करने की घोषणा कर दी क्योंकि ट्रंप समझ गए कि भारत का विशाल बाजार उनके हाथ से निकल रहा है।

- घोषणा अमेरिका की तरफ से हुई और डील भी बेहद आकर्षक थी, ऐसे में भारत के इन्कार करने का सवाल नहीं था।

- पर अब देखना यह है कि वास्तव में यह डील क्या रूप लेती है और भारत को कितना लाभ देगी।

विचार बिन्दु

बच्चों को पालना, उन्हें अच्छे व्यवहार की शिक्षा देना भी सेवाकार्य है, क्योंकि यह उनका जीवन सुखी बनाता है। –स्वामी रामसुखदास

लोकलुभावन नहीं 2047 के भारत की इबारत है नया बजट

संभवतः यह पहला अवसर होगा जब केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करते समय चुनावों में राजनीतिक लाभ हानि पर विचार किये बिना समग्र विकास और दीर्घकालीन आर्थिक सुधार को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया है। कुछ माहों में ही पं. बंगाल, तमिलनाडू, केरल, असम और पुडुचेरी के चुनाव की तिथियां घोषित हो जाएगी। अब तक होता यह आया है कि बजट में चुनाव वाले राज्यों के नागरिकों को लुभाने के लिए खास घोषणाएं होती हैं। पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजनीतिक लाभ हानि के स्थान पर समग्र सुधारों और सरकार के मिशन 2047 को केन्द्र में रखकर 2027-28 का बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वां बजट पेश किया है। खासबात यह कि 2019 से 2026 तक लगातार नवां बजट पेश करने तक वित्त मंत्री सीतारमण भिन्न भिन्न प्रदेशों की हथकरघा साड़ियों में नजर आई है। इस बार तमिलनाडू की बैंगनी कांजीवरम सिल्क साड़ी में नवां बजट पेश किया।

इस साल का बजट इसलिए भी मायने रखता है कि दुनिया के देशों के हालात और वैश्विक परिस्थितियां दिन प्रतिदिन विपरीत होती जा रही हैं। बजट के दिन जहां शेयर बाजार धराशाही हो गया वहीं दूसरे दिन ही अमेरिका द्वारा टैरिफ दर कम करने के साथ ही शेयर बाजार ने उंची उड़ान भर डाली। पर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए भारत की आर्थिक विकास की गति बनाए रखना किसी गंभीर चुनौती से कम नहीं है। विपरीत हालातों में भी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हमारी है। दुनिया के देश जहां आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था ने उंचाई प्राप्त की है। अमेरिका में ट्रंप 2 के बाद से दुनिया के हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं पर जिस रणनीति से भारत ने अमेरिका को इन्फोर की नीति पर चलते हुए चुनौती दी इसी का परिणाम है कि ट्रंप को टेरिफ दरें घटानी पड़ी है। हालांकि ट्रंप के मिजाज को देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब बह पलटी मार जाए।

केन्द्रीय बजट की इसलिए सराहना की जानी चाहिए कि वैश्विक हालातों को देखते हुए दीर्घकालीन आर्थिक सुधार, देश में ढांचगत विकास और युवाओं, महिलाओं, किसानों सभी को साधने का जो समग्र प्रयास हुआ है उससे निश्चित रूप से आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को नई दिशा मिलेगी। विश्लेषक इसे समग्र सुधारों के साथ विकास का संकल्प बता रहे हैं तो कोई इस बजट को भारत की

कहने को लाख आलोचनाएं की जा सकती हैं पर वैश्विक हालातों को देखते हुए जिस तरह का भविष्योन्मुखी ठोस आधारभूत विकास का बजट होने से इससे दीर्घकालीन लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था को बूस्ट प्राप्त होगा। सबसे खास बात यह है कि इस बजट के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि लोकलुभावन ही नहीं आमजन दीर्घकालीन आर्थिक विकास के बजट का आगे बढ़कर स्वागत करते हैं। अब बजटीय व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन का भी समयबद्ध रोडमैप बन जाए तो निश्चित रूप से इसका वास्तविक लाभ मिल सकेगा।

युद्ध में बदल जाएं कहा नहीं जा सकता है और पाकिस्तान कब अपनी उद्दंडता दिखा दे कुछ कहा नहीं जा सकता, चीन के इरादे हमेशा संदिग्ध रहे हैं ऐसे में रक्षा क्षेत्र में बजटीय प्रावधान बढ़ाना और सैन्य क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाना समय की मांग है। इसी तरह से डिजिटल युग में दुनिया के देशों से दो कदम आगे बढ़ना समय की मांग है। एआई के युग को देखते हुए एआई को रोजगार का माध्यम बनाना, कौशल विकास, तकनीक से शिक्षा को जोड़ने, पर्यटन विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, यहां तक कि गाइड्स तैयार करने से लेकर चुनावों और रोजगार से जुड़े सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के प्रावधान किये गये हैं। खेती-किसानी को प्रोत्साहित करने के साथ ही जल के महत्व को समझा गया है। अमृत सरोवर से जल संग्रहण से लेकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए बेहतर लोजिस्टिक प्रमुख आवश्यकता है। रक्षा के बाद सबसे अधिक प्रावधान बेहतर कनेक्टिविटी को दिया गया है। बेहतर आवागमन से विकास को गति मिलती है तो योजनाबद्ध शहरी विकास पर जोर दिया गया है। यदि सार रूप में कहा जाए तो यह बजट आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने का रोडमैप कहा जा सकता है। विनिर्माण क्षेत्र को गति, आधारभूत संरचना विकास, कौशल विवकास, एमएसएमई को प्रोत्साहन, उर्जा विकास व सहज उपलब्धता, इकोसिस्टम बनाए रखते हुए समग्र विकास पर जोर रहा है। हालांकि नौकरी पेशा लोग आयकर में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करने से निराश हुए हैं तो शेयर मार्केट में सर्ट्देबाजी को निरुत्साहित करने से निराशा हुई और इसका तत्काल असर शेयर बाजार पर देखा गया। कहने को लाख आलोचनाएं की जा सकती है पर वैश्विक हालातों को देखते हुए जिस तरह का भविष्योन्मुखी ठोस आधारभूत विकास का बजट होने से इससे दीर्घकालीन लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था को बूस्ट प्राप्त होगा। सबसे खास बात यह है कि इस बजट के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि लोकलुभावन ही नहीं आमजन दीर्घकालीन आर्थिक विकास के बजट का आगे बढ़कर स्वागत करते हैं। अब बजटीय व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन का भी समयबद्ध रोडमैप बन जाए तो निश्चित रूप से इसका वास्तविक लाभ मिल सकेगा।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(वरिष्ठ लेखक)

राशिफल

शुक्रवार 6 फरवरी, 2026

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, हस्त नक्षत्र रात्रि 12:2 तक, धृति योग रात्रि 11:37 तक, कौलव करण दिन 12:51 तक, चन्द्रमा आज कन्या राशि में संचार करेगा।

गृहस्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरु-मिथुन, शुक्र-कुम्भ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह आज कुमार योग सूर्योदय से रात्रि 12:24 तक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:36 तक, लाभ-अमृत 8:36 से 11:19 तक, शुभ 12:41 से 2:03 तक, चर 4:46 से सूर्यास्त तक।
राहुकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:14, सूर्यास्त 6:08



मेघ

परिवार में चल रहे आपसी मतभेद दूर होंगे। अस्त-व्यस्त दिवचार्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



तुला

व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। नौकरपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आर्थिक मामलों में पेशानी हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा।



वृष

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



वृश्चिक

आय में वृद्धि होगी। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।



मिथुन

घर-परिवार में सुख-शान्ति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।



धनु

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



कर्क

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रो/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।



मकर

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



सिंह

आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।



कुंभ

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है।



कन्या

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।



मीन

परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

ट्रंप डील और मोदी नेतृत्व

राजस्थान के उद्योग के लिए नए अवसरों का द्वार



अशोक परनामी

भारत और अमेरिका के बीच लंबे इंतजार के बाद संपन्न हुई नई ट्रेड डील ने न केवल दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई दी है, बल्कि राजस्थान जैसे निर्यात-आधारित राज्यों के लिए यह समझौता उम्मीदों का नया क्षितिज खोलता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय उत्पादों पर टैरिफ की घटाकर 18 प्रतिशत करने का निर्णय ऐसे समय आया है, जब वैश्विक बाजार में अस्थिरता और संरक्षणवाद

की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। इस पृष्ठभूमि में यह समझौता भारत की बढ़ती वैश्विक साख और प्रभावी आर्थिक कूटनीति का प्रमाण माना जा रहा है। इस ऐतिहासिक समझौते के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बीते एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद वैश्विक साझेदार के रूप में स्थापित किया है। 'मेक इन इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसे अभियानों को अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता दिलाने में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। अमेरिका जैसे प्रभावशाली देश द्वारा टैरिफ में इतनी बड़ी कटौती इस बात का संकेत है कि भारत अब शर्तें तय करने वाली अर्थव्यवस्था बन रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इस डील को 'गेम चेंजर' करार देना भी इसी तथ्य को रेखांकित करता है कि केंद्र के मजबूत नेतृत्व का सीधा लाभ राज्यों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले छह वर्षों में

नौ महत्वपूर्ण ट्रेड डील कर यह साबित किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंच पर खड़ी है। टैरिफ कटौती का सीधा और तात्कालिक असर राजस्थान के ज्वेलरी, हैडीक्राफ्ट, गारमेंट और स्टोन उद्योगों पर दिखाई देने लगा है। उद्योग संगठनों के अनुसार, टैरिफ बढ़ने के बाद राज्य का निर्यात करीब 50 प्रतिशत तक गिर गया था। कई इकाइयां बंद होने की कगार पर थीं और हजारों कारीगरों व श्रमिकों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा था। अब अमेरिकी बाजार से दोबारा पूछताछ और ऑर्डर मिलना शुरू होने से उद्योग जगत में नया उत्साह है।

जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में फैला जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग राजस्थान की वैश्विक पहचान का प्रतीक है। रंगीन पत्थरों और पारंपरिक राजस्थानी डिजाइनों की अंतरराष्ट्रीय मांग टैरिफ वृद्धि के कारण लगभग ठग ही गई थी। उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों का कहना है कि टैरिफ घटने के बाद अमेरिका सहित अन्य बाजारों से मांग लौटने लगी है। इससे कारीगरों और निर्यातकों को नई

ऊर्जा मिली है। अमेरिका जैसे बड़े खरीदार पर काफी हद तक निर्भर स्टोन इंडस्ट्री टैरिफ बढ़ने से सबसे अधिक प्रभावित हुई थी। 70 प्रतिशत से अधिक इकाइयों पर इसका नकारात्मक असर पड़ा। अब टैरिफ कटौती के बाद अमेरिकी खरीदारों की सक्रियता बढ़ने से उत्पादन और रोजगार दोनों में सुधार की उम्मीद है। इसी तरह तीन लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने वाला जयपुर का गारमेंट उद्योग एक बार फिर रफ्तार पकड़ने को तैयार है। निर्यात में गिरावट से जूझ रहे एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से राहतभरा साबित हो रहा है।

राजस्थान का हस्तशिल्प, ब्लू पॉटरी, लकड़ी का काम, संगमरमर की नक्काशी और हाथ से बने वस्त्र अमेरिकी बाजार में लोकप्रिय रहे हैं। टैरिफ घटने से जयपुर और जोधपुर के कारीगरों को बेहतर दाम और स्थिर बाजार मिलने की संभावना है। यह न केवल आर्थिक लाभ देगा, बल्कि सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी

सहायक होगा। निर्यात में वृद्धि का असर केवल उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा। परिवहन, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, बैंकिंग और बीमा जैसे सहायक क्षेत्रों में भी गतिविधियां बढ़ेंगी। यह 'मल्टीप्लायर इफेक्ट' राजस्थान की अर्थव्यवस्था को व्यापक गति देगा और नए रोजगार सृजित करेगा।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील और टैरिफ में ऐतिहासिक कटौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट दृष्टि और प्रभावी आर्थिक कूटनीति का परिणाम है। राजस्थान के लिए यह समझौता केवल व्यापारिक राहत नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ वैश्विक बाजार में आगे बढ़ने का अवसर है। यदि राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों के साथ उद्योग जगत इस अवसर का सही उपयोग करता है, तो राजस्थान आने वाले वर्षों में निर्यात के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकता है और यही इस डील की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।

–अशोक परनामी,
पूर्व विधायक एवं
पूर्व मेयर जयपुर।

तारबंदी से सुरक्षा, बीमा से संबल : किसानों को करोड़ों रुपये का अनुदान मिला

विकसित भारत 2047 के सपने के केंद्र में अन्नदाता : सरकारी सहायता और योजनाओं ने खोले रास्ते, किसान ने दुनिया देखी



अमृता कटारा

भारतीय कृषि को अक्सर परंपरा के फ्रेम में बाँधकर देखा गया है-हल, बैल, मानसून और अनिश्चितता। लेकिन आज खेतों की ज़मीन के नीचे सिर्फ बीज नहीं, बदलाव भी दबाहुआ है। यह बदलाव न तो अचानक है और न ही पूरी तरह दृश्यमान होता है। यह धीरे-धीरे किसान की सोच, नीति और खेती में बदलाव की कोशिश कर रही है। एक ओर रक्षा बजट की कोशिश कर रही है। जिस तरह के तनाव के हालात बने हुए हैं और हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के हालात हैं, उधर रुस यूक्रेन युद्ध थमने का ही नाम नहीं ले रहा है, ईरान अमेरिका के हालात कब

युद्ध में बदल जाएं कहा नहीं जा सकता है और पाकिस्तान कब अपनी उद्दंडता दिखा दे कुछ कहा नहीं जा सकता, चीन के इरादे हमेशा संदिग्ध रहे हैं ऐसे में रक्षा क्षेत्र में बजटीय प्रावधान बढ़ाना और सैन्य क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाना समय की मांग है। इसी तरह से डिजिटल युग में दुनिया के देशों से दो कदम आगे बढ़ना समय की मांग है। एआई के युग को देखते हुए एआई को रोजगार का माध्यम बनाना, कौशल विकास, तकनीक से शिक्षा को जोड़ने, पर्यटन विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, यहां तक कि गाइड्स तैयार करने से लेकर चुनावों और रोजगार से जुड़े सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के प्रावधान किये गये हैं। खेती-किसानी को प्रोत्साहित करने के साथ ही जल के महत्व को समझा गया है। अमृत सरोवर से जल संग्रहण से लेकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए बेहतर लोजिस्टिक प्रमुख आवश्यकता है। रक्षा के बाद सबसे अधिक प्रावधान बेहतर कनेक्टिविटी को दिया गया है। बेहतर आवागमन से विकास को गति मिलती है तो योजनाबद्ध शहरी विकास पर जोर दिया गया है। यदि सार रूप में कहा जाए तो यह बजट आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने का रोडमैप कहा जा सकता है। विनिर्माण क्षेत्र को गति, आधारभूत संरचना विकास, कौशल विवकास, एमएसएमई को प्रोत्साहन, उर्जा विकास व सहज उपलब्धता, इकोसिस्टम बनाए रखते हुए समग्र विकास पर जोर रहा है। हालांकि नौकरी पेशा लोग आयकर में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करने से निराश हुए हैं तो शेयर मार्केट में सर्ट्देबाजी को निरुत्साहित करने से निराशा हुई और इसका तत्काल असर शेयर बाजार पर देखा गया। कहने को लाख आलोचनाएं की जा सकती है पर वैश्विक हालातों को देखते हुए जिस तरह का भविष्योन्मुखी ठोस आधारभूत विकास का बजट होने से इससे दीर्घकालीन लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था को बूस्ट प्राप्त होगा। सबसे खास बात यह है कि इस बजट के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि लोकलुभावन ही नहीं आमजन दीर्घकालीन आर्थिक विकास के बजट का आगे बढ़कर स्वागत करते हैं। अब बजटीय व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन का भी समयबद्ध रोडमैप बन जाए तो निश्चित रूप से इसका वास्तविक लाभ मिल सकेगा।

शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कृषि की नीति के केंद्र में रखा है। किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, पीएम-कुसुम, अटल भू-जल योजना, किसान डिजिटल आईडी, तारबंदी और जैविक खेती जैसी योजनाएँ यह संकेत देती हैं कि सरकार ने खेती को अल्पकालिक राहत नहीं, बल्कि दीर्घकालिक योजना मानती है।

राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल में लगभग 59 हजार 039 सोलर पंपसेटों की स्थापना कर 900 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया जाना यह बताता है कि सिंचाई और नवीनीकरण ऊर्जा के सवाल को स्थायी समाधान की ओर ले जाया जा रहा है। इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 6,450 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम का वितरण यह दर्शाता है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय किसान को आर्थिक सुरक्षा देने का प्रयास किया गया है। खेती में जोखिम कम हुए बिना नवाचार संभव नहीं होता। नीति का असर तब स्पष्ट दिखता है जब वह ज़मीन पर उतरती है।

राजस्थान में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर इस मायने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं। योजनाओं की जानकारी, आवेदन की प्रक्रिया और समस्याओं का समाधान-सब कुछ एक ही मंच पर उपलब्ध होने से किसानों और प्रशासन के बीच की दूरी कम हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि जागरूकता केवल सूचना से नहीं, संवादसे आती है और यही इन शिविरों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रतापगढ़ जैसे जनजाति क्षेत्रों में यह बदलाव विशेष महत्व रखता है, जहाँ खेती लंबे समय तक केवल जीवननिर्वाह तक सीमित रही। छोटी ज़ोतों और सीमित संसाधनों के बीच प्रतापगढ़ के जवाहरनगर के बाबूलाल मीणा द्वारा सरकार की सहायता से वर्मी कम्पोस्ट यूनित की स्थापना यह बताती है कि जैविक खेती अब प्रयोग नहीं रही। कम लागत, बेहतर मूल्य और अतिरिक्त आय-ये



परिणाम बताते हैं कि सही मार्गदर्शन मिलने पर किसान टिकाऊ विकल्पों की ओर बढ़ सकता है।

इसी जिले से किसान शंभूलाल पाटीदार का डेनमार्क एक्सपोजर विजिट पर जाना यह संकेत देता है कि कृषि प्रशिक्षण अब केवल तकनीक सिखाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोच का दायरा भी बढ़ा रहा है। जब किसान दुनिया को देखने लगता है, तो अपनी ज़मीन को देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। तारबंदी योजना ने भी खेती को स्थिरता दी है एवं किसानों के हितों की रक्षा की है। जवाहरनगर की दुर्गा बाई मीणा और पिल्लू गाँव के पंकज कुमार मीना जैसे किसानों की कहानियाँ यह बताती हैं कि फसल सुरक्षा केवल नुकसान नहीं रोकती बल्कि कृषि को अधिक सुरक्षित बनाती है।

राज्य में लगभग 34,395 किलोमीटर तारबंदी कर 377.66 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाना इस बात का संकेत है कि खेती को जोखिम से मुक्त करने की दिशा में ठोस प्रयास हुए हैं। इसके साथ ही 35,368 फार्म पॉन्ड के निर्माण पर 300 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान जल संरक्षण को खेती की बुनियाद बनाने की मंशा को दर्शाता है। इन सभी अनुभवों और आँकड़ों को साथ रखकर देखा जाए तो स्पष्ट होता

है कि प्रदेश के अन्नदाताओं का भविष्य जनहितैषी कार्यों की निरंतरता, ज़मीनी क्रियान्वयन और किसान की भागीदारी से आकार ले रहा है। खेत आज भी परंपरा से जुड़े हैं, लेकिन अब उनके साथ सुरक्षा, ज्ञान और उम्मीद भी खड़ी है-और शायद यही बदलाव की सबसे बड़ी पहचान है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा कृषि को नवाचार, सुरक्षा और सम्मान से जोड़ने की दिशा में जो व्यापक विजन सामने रखा, उसे राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ज़मीन पर आकार मिलता दिख रहा है। सोलर पंप से लेकर फसल बीमा, तारबंदी से लेकर जल संरक्षण तक-ये प्रयास यह संकेत देते हैं कि किसान को अब केवल उत्पादन की इकाई नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सहभागी माना जा रहा है। जनजाति क्षेत्रों से सामने आई बदलाव की यह कहानियाँ यह भरोसा जगाती हैं कि जब नीति में निरंतरता हो और क्रियान्वयन में संवेदनशीलता, तो खेती केवल अतीत की विरासत नहीं रहती, वह भविष्य की बुनियाद बन जाती है।

शंभू लाल पाटीदार: वैश्विक अनुभव और सरकारी योजनाओं से बदली खेत की तस्वीर

प्रतापगढ़ जिले के प्रगतिशील किसान शंभू लाल पाटीदार ने पारंपरिक

खेती को आधुनिक और लाभकारी कृषि में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है। उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी खेती को नई दिशा दी। सरकारी सहयोग से वे पॉलीहाउस में लाल और हरी शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें अधिक उत्पादन के साथ बेहतर बाजार मूल्य भी मिल रहा है। उनकी यह सफलता इस बात का उदाहरण है कि सही तरीके से लागू की गई सरकारी योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ टिकाऊ और नवाचारी कृषि को भी बढ़ावा देती हैं।

हाल ही में शंभू लाल पाटीदार को एक सरकारी कार्यक्रम के तहत डेनमार्क जाने का अवसर मिला, जहाँ उन्होंने उन्नत जैविक खेती की तकनीकों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने इस अनुभव को अत्यंत लाभकारी बताते हुए कहा कि वहां उन्होंने उत्पादन बढ़ाने और खेती में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के कई महत्वपूर्ण गुर सीखे। सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल किसानों को वैश्विक ज्ञान, नई दक्षताएं और नवाचार करने का आत्मविश्वास प्रदान करती हैं।

–अमृता कटारा,
एपीआरओ, डीआईपीआर

बोर्ड परीक्षाओं के लिए कंट्रोल रूम शुरु

अजमेर, (निर्स)। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के सफल, निष्पक्ष एवं सुचारु आयोजन को लेकर गुरुवार को कंट्रोल रूम की स्थापना की गई। इस अवसर पर बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने विधि-विधान के साथ मां सरस्वती की पूजा-अर्चना कर कंट्रोल

बोर्ड का शुभारंभ किया। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि कंट्रोल रूम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य परीक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना तथा परीक्षा के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। कंट्रोल रूम

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में स्थापित किया गया है, जहाँ से पूरे प्रदेश की परीक्षा गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि कंट्रोल रूम के लिए चार अलग-अलग लैडलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इन नंबरों के माध्यम से प्रदेश भर के परीक्षा केंद्र

अधीक्षक एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी परीक्षा के दौरान आने वाली किसी भी प्रकार की परीक्षा, अव्यवस्था या आपात स्थिति की जानकारी सीधे कंट्रोल बोर्ड को दे सकेंगे। प्राप्त सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बोर्ड प्रशासन का मानना है कि कंट्रोल बोर्ड की सक्रिय



पंडित अनिल शर्मा

गृहस्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरु-मिथुन, शुक्र-कुम्भ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह आज कुमार योग सूर्योदय से रात्रि 12:24 तक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:36 तक, लाभ-अमृत 8:36 से 11:19 तक, शुभ 12:41 से 2:03 तक, चर 4:46 से सूर्यास्त तक।
राहुकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:14, सूर्यास्त 6:08



मेघ

परिवार में चल रहे आपसी मतभेद दूर होंगे। अस्त-व्यस्त दिवचार्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



तुला

व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। नौकरपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आर्थिक मामलों में पेशानी हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा।



वृष

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



सार-समाचार

होलिका दहन के दिन बोर्ड परीक्षा अत्यावहारिक - गंगवाल

अजमेर(निस्)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 2 मार्च को कक्षा 1०वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित किए जाने पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सीए प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री सीए विकास अग्रवाल एवं अजमेर शहर व्यापार महासंघ के प्रवक्ता कमल गंगवाल ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि 2 मार्च को होलिका दहन एवं 3 मार्च को धुलंडी का पर्व राज्यभर में अ्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। ऐसे प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक पर्व के दिन परीक्षा आयोजित करना लाखों छात्रों और अभिभावकों के लिए मानसिक तनाव और असमंजस की स्थिति उत्पन्न करेगा। सीए अग्रवाल एवं गंगवाल ने सीबीएसई अध्यक्ष एवं परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज से छात्र हित एवं सामाजिक संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा तिथि में तत्काल संशोधन की मांग की है। शरद कपूर एवं प्रहलाद माथुर ने भी कहा कि होली के जैसे राष्ट्रीय पर्व पर परीक्षा लेना तो ब्यावहारिक है और न ही संवेदनशील है।

मेधा शर्मा का जयपुर में प्रतिष्ठित टेक्सटाइल कंपनी में चयन

ब्यावर (निस्)। शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति करते हुए वर्धमान इंस्टीट्यूटयू ऑफ फैशन डिजानिंग एवं मेकअप आर्टिस्ट विभाग की एक और छात्रा ने सफलता का परचम लहराया है। संस्थान के फैशन डिजानिंग विभाग की छात्रा मेधा शर्मा का चयन ओ यूमनिया टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, जयपुर में हुआ है। यह उपलब्धि न केवल मेधा शर्मा के लिए, बल्कि पूरे संस्थान के लिए गर्व और खुशी का विषय है।मेधा शर्मा ने अपने प्रशिक्षण काल के दौरान फैशन डिजानिंग के विभिन्न पहलुओं जैसे फैब्रिक स्टडी, टेक्सटाइल डिजाइन, पैटर्न मैकिंग एवं प्रैक्टिकल वर्क में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. आर. सी. लोहा ने मेधा शर्मा को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि वर्धमान इंस्टीट्यूटयूट विद्यार्थियों को केवल शैक्षणिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि उद्योग-उन्मुख एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि छात्रा का चयन यह सिद्ध करता है कि संस्थान द्वारा दी जा रही शिक्षा आज के फैशन और टेक्सटाइल उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप है।वर्द्धमान शिक्षण समिति के मंत्री डॉ नरेंद्र पारख ने भी मेधा शर्मा को इस सफलता पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि अन्य छात्राओं के लिए प्रेरणास्त्रोत बनेगी और इससे संस्थान की साख और अधिक मजबूत होगी।

आम आदमी पार्टी ने डाक अधीक्षक को साँपा ज्ञापन

ब्यावर (निस्)। आम आदमी पार्टी ब्यावर द्वारा डाक अधीक्षक कमलेश प्रजापत को ज्ञापन साँपा गया। ज्ञापन में मुख्य रूप से ब्यावर जिले बनने के ढाई वर्ष बाद भी 2४ 7 दिन रात डाक सेवाएं शुरू नहीं की गई है जबकि अजमेर में रेलवे स्टेशन पर 2४ 7 दिन रात डाक सेवाएं रहती है। उसी तर्ज पर ब्यावर में भी रेलवे स्टेशन पर 2४ 7 डाक सेवाओं की मांग का ज्ञापन आम आदमी पार्टी ब्यावर ने अधीक्षक डाक विभाग ब्यावर को साँपा। ज्ञापन में जिला न्यायालय ब्यावर में भी अलग से डाक काउंटर लगवाने की मांग भी रखी जिस पर अधीक्षक महोदय ने दोनो विषयों पर कार्यवाही करने का जनहित को सर्वोपरि रखते हुए आश्वासन दिया।ब्यावर जिला बनने के बाद प्रशासनिक, व्यवसायिक एवं सामाजिक गतिविधियों में निरन्तर वृद्धि हुई है जिससे 2४ ग 7 डाक सेवाएं अति आवश्यक हो गई है। इसके अभाव में अधिवक्ताओं, व्यापारियों, विद्यार्थियों एवं शासकीय कार्यों से जुड़े लोगो को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा है। शिष्टमण्डल में पार्टी जिलाध्यक्ष शौकीन काठाट, ट्रेड विंग जिलाध्यक्ष शंकर प्रजापति, एस सी विंग जिलाध्यक्ष नारायण अग्रवाल, ओबीसी विंग जिलाध्यक्ष बाबुलाल घैल, शहर अध्यक्ष धीरज जैन , डॉ. कमल पुरोहित, राधावल्लभ माहेश्वरी, खीयाराम सिंगारिया, कन्हैयालाल खत्री, मुराद काठाट, धर्मेन्द्र कुमारत, गोपी काठाट, राजू रावत, एडवोकेट नीलेश बुरड़ आदि उपस्थित रहे।

वाल्मीकि समाज को मिले सफाईकर्मियों की भर्ती में प्राथमिकता

भीलवाड़ा (निस्)। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने आज राजस्थान विधानसभा में स्थान प्रस्ताव के माध्यम से प्रदेश में सफाईकर्मियों की लंबित भर्ती और वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। विधायक कोठारी ने अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान और कचरा मुक्त भारत जैसे राष्ट्रीय अभियानों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश स्तर पर स्वच्छता को जन अंदोलन बनाया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर सफाईकर्मियों की कमी के कारण इन अभियानों की भावना पूरी तरह साकार नहीं हो पा रही है। विधायक कोठारी ने सदन में कहा कि जब कोई व्यक्ति सुबह घर से निकलता है और सड़क व नालियां गंदी दिखती हैं तो वह सबसे पहले स्थानीय जनप्रतिनिधि और सरकार को दोष देता है, जबकि वास्तविक समस्या सफाईकर्मियों की अपर्याप्त संख्या है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2०18 के बाद से सफाईकर्मियों की नियमित भर्ती नहीं हुई है। पिछले वर्ष भर्ती का प्रयास भी अनुभव प्रमाण पत्र जैसी कृत्रिम अड़चनों के कारण निरस्त करना पड़ा। कोठारी ने विशेष रूप से वाल्मीकि समाज का उल्लेख करते हुए कहा कि यह समाज परंपरागत रूप से सफाई कार्य से जुड़ा रहा है। ऐसे में इस समाज के लोगों से अनुभव प्रमाण पत्र मांगना व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने कहा कि जब अन्य समाज के व्यक्तियों का चयन सफाईकमी के रूप में होता है तो वे अक्सर मूल सफाई कार्य के स्थान पर अन्य कार्यों में लग जाते हैं, जिससे सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है। उन्होंने संविदा पर कार्यरत सफाईकर्मियों की स्थिति पर भी चिंता जताते हुए कहा कि वे शोषण पूर्ण परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं।

मांडल में लैंगिक भेदभाव पर जागरूकता कार्यशाला

भीलवाड़ा(निस्)। बाल व महिला चेतना समिति तथा डायरेक्ट एक्शन फॉर वुमैन नाउ के संयुक्त तत्वाधान में रूपी देवी कॉलेज, मांडल में छात्राओं के लिए लैंगिक भेदभाव एवं जेंडर समानता विषय पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. ज्योति द्वारा अतिथियों के स्वागत एवं परिचय से हुई। उन्होंने कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए छात्राओं को इस विषय की प्रासंगिकता से अवगत कराया। संस्था अध्यक्ष द्वारा अहलूवालिया ने कहा कि कम उम्र में ही जेंडर से जुड़े मुद्दों को समझना बेहद जरूरी है, ताकि समाज में समानता की संघर्ष की मजबूत किया जा सके। कार्यशाला की मुख्य वक्ता उदयपुर से आई शशिप्रभा ने छात्राओं को दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों के माध्यम से जेंडर की अवधारणा को बेहद सरल और प्रभावी ढंग से समझाया। उन्होंने पर-परिवार में लड़का-लड़की के बीच किए जाने वाले भेदभाव, काम के बंटवारे, शिक्षा और कैरियर से जुड़े सामाजिक नजरिए पर विस्तार से चर्चा की। शशि जी ने बताया कि जेंडर समानता केवल महिलाओं का विषय नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उनके संवादात्मक अंदाज ने छात्राओं को सोचने, संवाद करने और अपनी बात रखने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में कॉलेज की सचिव टीना गुर्जर ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाओं से विद्यार्थियों की मुद्दे के प्रति संवेदनशीलता और समझ विकसित होती है।

विश्व कैसर दिवस पर जागरूकता सत्रों का किया आयोजन

भीलवाड़ा(निस्)। विश्व कैसर दिवस के अवसर पर, हिंदुस्तान ज़िंक लिमिटेड के सीएसआर विभाग के सहयोग से ममता एचआईएमसी द्वारा संचालित मोबाइल हेल्थ चैन प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान एवं उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कैसर जागरूकता और स्क्रीनिंग शिविरों का आयोजन किया गया। यह अभियान मुख्य रूप से पांच प्रमुख स्थानों उदयपुर के जावर, राजसमंद के दरीबा, चित्तौड़गढ़ के चंदेरीया, भीलवाड़ा के आगुवा एवं उत्तराखंड के पंतनगर ऊधम सिंह नगर में आयोजित कियाे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कैसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बीमारी के शुरुआती लक्षणों की पहचान करना और समय पर इलाज की महत्व को समझाना था। विशेष रूप से महिलाओं और तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों को मुंह, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैसर के खतरों के प्रति जागरूक किया गया।

केशव एच. कुणकर्णी की स्मृति में 2०वां विशाल रक्तदान शिविर

अजमेर(निस्)। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर मंडल के तत्वावधान में श्रद्धेय स्वर्गीय केशव एच. कुणकर्णी की स्मृति में 20वां विशाल रक्तदान शिविर सीनियर रेलवे इंस्टिट्यूटयू, अजमेर में आयोजित किया गया। शिविर का आयोजन प्रात: 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया गया, जिसमें कर्मचारियों एवं उनके परिजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

अजमेर शिविर में 495 लोगों ने रक्तदान के लिए पंजीकरण कराया, जिनमें से 465 ने रक्तदान किया। इनमें 15 महिलाएं भी शामिल रहीं, जबकि 3० लोगों को स्वास्थ्य एवं अन्य कारणों से अयोग्य घोषित किया गया। इसी प्रकार आबूरोड़ में 2०1 लोगों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 175 ने रक्तदान किया और 26 लोग अयोग्य पाए गए। इस प्रकार

दो मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में एक व्यक्ति घायल

मसूदा , (निस्)। मसूदा थाना क्षेत्र में दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़ंत में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर राहगीरों ने 1०8 एंबुलेंस को बुलाया। एंबुलेंस चालक राजेंद्र एवं कंपांडर योगेश शर्मा घायल को मसूदा उप जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। घायल की हालत गंभीर होने पर उसे उच्च चिकित्सा प्रभावित को लिए रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवपुरा निवासी शैतान मोटरसाइकिल से घरेलू सामान लेने जा रहा था, तभी सामने से तेज गति से आ रही मोटरसाइकिल से उसकी टक्कर हो गई। खबर लिखे जाने तक घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी।



रक्तदान शिविर में कर्मचारियों एवं उनके परिजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कुल 64० यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतडा तथा विशेष अतिथि विकास आनंद, मुख्य कारखाना

प्रबंधक अजमेर रहे। कार्यक्रम में

महामंत्री विनोद मेहता सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए

राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की जिला कार्यकारिणी में पदों पर मनोनयन

■ **जिला कार्यकारिणी के चुनाव के बाद शेष रहे पदों का सहवर्त संगठन की सहमति से किया गया**

जिला अध्यक्ष धर्मेष्ट सिंह नरूका ने बताया कि जिला कार्यकारिणी के चुनाव के बाद शेष रहे पदों का सहवरण संगठन की सहमति से किया गया, जिससे जिला कार्यकारिणी अब पूर्ण रूप से गठित हो गई है।

मनोनयन के तहत अतिरिक्त जिला मंत्री पद पर भरत सिंह पंवार को दायित्व सौंपा गया। उपाध्यक्ष संस्कृत शिक्षा के पद पर लेखराज जाट, उप जिला निरीक्षक अजमेर को नियुक्त किया गया। सचिव संस्कृत शिक्षा के रूप में विमल कुमार जैन, प्रधानाचार्य संस्कृत विद्यालय अजमेर

को जिम्मेदारी दी गई। प्रधानाचार्य प्रतिनिधि के रूप में सुरेंद्र पाल सिंह चौधरी, केसरपुरा को मनोनीत किया गया।

इसी क्रम में महिला शिक्षक प्रतिनिधि पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

42 वाँ वार्षिकोत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह

किसी भी प्रलेख की कमी के कारण अथवाजिन शालाओं ने बोर्ड से सम्बद्धता का वार्षिक शुल्क जमा नहीं कराया है। उनके प्रवेश पत्र बोर्ड कार्यालय द्वारा अपलोड नहीं किए जाएंगे। शाला द्वारा जिन छात्रों का नाम एनएसओ, उपस्थिति न्यून अथवा अन्य कारण से रोका जाना है अथवा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है ऐसे छात्रों को प्रवेश पत्र वितरित नहीं करें। यदि ऐसे प्रवेश पत्र वेबसाईट पर अपलोड हो गए हैं तो शाला प्रधान कमियों वाले प्रवेश पत्रों को अपने स्तर

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दायित्व दिया गया। प्रबोधक प्रतिनिधि के पद पर योगेश्वर

पारीक, अराई को मनोनीत किया गया।

जिला मंत्री पद पर मीना शर्मा, सराधना को चुना गया। प्रयोगशाला सहायक

प्रतिनिधि के रूप में विष्णु पाराशर, पुष्कर को दाय

उद्यिमयों के साथ मिलकर पत्थर उद्योग को देश में सिरमौर बनाएंगे : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जेईसीसी में इंडिया स्टोन मार्ट का उद्घाटन किया

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के पत्थरों की विशिष्टता को विश्व पटल पर अनूठी पहचान है। देशभर के अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों, किलों, महलों में राजस्थान का पत्थर उपयोग में लाया गया है। अब राजस्थान का पत्थर उद्योग नई ऊंचाइयों छूने के लिए पूरी तरह तैयार है। तथा हम इस उद्योग को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने सभी

- मुख्यमंत्री ने स्टोन क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले उद्यिमयों को किया सम्मानित

- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किशनगढ़ का मार्बल,राजसमंद, जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के पत्थर दुनियाभर में प्रसिद्ध हैं

उद्यिमयों से प्रदेश में मिलकर पत्थर उद्योग को देश में सिरमौर बनाने की अपील की।शर्मा गुरुवार को जयपुर के जेईसीसी में आयोजित इंडिया स्टोन मार्ट के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सीडॉस, रीको और लघु उद्योग भारती को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि इंडिया स्टोनमार्ट प्रदर्शनी नए राजस्थान के संकल्प का प्रतीक है। यह आयोजन भारतीय प्राकृतिक पत्थर उद्योग की शक्ति और सामर्थ्य को प्रदर्शित करने का



मुख्यमंत्री ने स्टोन क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले निदेशक अनिल चौधरी तथा मुकेश चंद्र अग्रवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया।

एक वैश्विक मंच बन चुका है। उन्होंने कहा कि इस स्टोन मार्ट का पहली बार 26 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में वेबसाइट निर्माण, डिजिटल मोबाइल एप्लीकेशन तथा विशाल क्षेत्र में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विपुल खनिज संपदा है। यहां कुल 85 तरह के खनिज उपलब्ध है। मकराना का संगमरमर, किशनगढ़ का मार्बल सहित राजसमंद, जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के पत्थर दुनियाभर में प्रसिद्ध है। राजस्थान के पास न केवल समृद्ध संसाधन हैं, बल्कि सदियों पुरानी शिल्पकला की परंपरा भी है। साथ ही, हमारे कारीगरों की कला निश्चयविख्यात है। हमारे पत्थर को पर्यावरण के अनुकूल, टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामग्री के रूप

में अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति मिल रही है। उन्होंने कहा कि कहा कि उद्योग की असली ताकत हमारे कुशल कारीगर और मेहनतकश श्रमिक हैं। उनके हाथों की कारीगरी ही साधारण पत्थर को अद्भुत कला में बदलती है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर इकॉनोमी बनाया जाए।

इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कपल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार पत्थर उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। राज्य सरकार द्वारा निवेश परक नई नीतियों, सिंगल विंडो क्लियरंस, प्रक्रियाओं का सरलीकरण सहित विभिन्न नवाचारों के माध्यम से उद्यिमयों को राहत दी जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने

स्टोन क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले श्रीराम मेगा स्ट्रक्चर के निदेशक अनिल चौधरी तथा एवर शाइन मार्बल्स के प्रबंध निदेशक मुकेश चंद्र अग्रवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने इंडिया स्टोनमार्ट 2026 प्रदर्शनी का फीता खेलकर उद्घाटन किया एवं स्टॉल्स का अवलोकन किया।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, मुख्य सचिव जी. श्रीनिवास, लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री प्रकाशचंद्र, आर.के. मार्बल्स के चैयरमेन अशोक पाटनी, ईरान और टर्कई के प्रतिनिधिगण, सहित लघु उद्योग भारती के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, रीको एवं सीडॉस के अधिकारीगण, बड़ी संख्या में उद्यमी, वास्तुकार एवं श्रमिक मौजूद रहे।

अधिकारी दीर्घा खाली मिलने पर स्पीकर वासुदेव देवनानी नाराज़

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को उस समय हंगामे जैसे हालात बन गए, जब शून्यकाल के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी दीर्घा में मौजूद नहीं पाए गए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे सदन की गरिमा के खिलाफ बताया। सदन की कार्यवाही सुबह ठीक 11 बजे शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी समय पर आसन पर पहुंचे और शून्यकाल की कार्यवाही प्रारंभ करवाई।

इसी दौरान उन्होंने देखा कि अधिकारी दीर्घा पूरी तरह खाली पड़ी हुई है। इस पर अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पूर्व में स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि शून्यकाल के दौरान संबंधित

इंडिया पिकफेस्ट में कलाकारों का लाइव प्रदर्शन

जयपुर । पिकफेस्ट का 5 वां संस्करण आज से आरम्भ हुआ। यह एक ऐसा उत्सव है जो हमें एक देश के रूप में परिभाषित करता है: एक ऐसा देश जो कहानियाँ सुनाता है, अपने देखा है, अपने सांस्कृतिक वैभव पर गर्व करने को प्रेरित करता है और अपनी कला, संस्कृति को सहेज कर युवा पीढ़ी को सौंपने की राह बनाता है। यह रंग, संस्कृति और रचनात्मक ऊर्जा का एक आंदोलन है।

इसमें कलावृत्त संस्था द्वारा आयोजित लघु चित्राल की कार्यशाला के साथ साथ अपनी अपनी कलाओं के सिद्धहस्त कलाकार शिल्पगुरु डॉ. इंंदरसिंह सिंह, नीरू छावड़ा, वीरन्द्र बन्नी एवं पृथ्वी राज कुम्हारत अपनी कला का लाइव डेमो द्वारा प्रदर्शित करेंगे तथा युवा पीढ़ी को उसकी तकनीक के बारे में भी बताएंगे और सीखने का भी प्रयास करेंगे।

जयपुर वासियों इस उत्सव का हिस्सा बनें और इसकी रचनात्मकता का अनुभव करें।

- देवनानी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे सदन की गरिमा के खिलाफ बताया। सदन की कार्यवाही सुबह ठीक 11 बजे शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी समय पर आसन पर पहुंचे और शून्यकाल की कार्यवाही प्रारंभ करवाई

- अध्यक्ष की नाराजगी के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सदन को आश्वासन दिया कि आगे से ऐसी स्थिति दोबारा नहीं बनेगी

विभागों के अधिकारी सदन में मौजूद रहेंगे, ताकि विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों पर तुरंत संज्ञान लिया जा सके।

उन्होंने कहा कि अधिकारी दीर्घा का खाली रहना गंभीर लापरवाही है और इसे तत्काल सुधारा जाना चाहिए। अध्यक्ष की नाराजगी के बाद संसदीय

कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सदन को आश्वासन दिया कि आगे से ऐसी स्थिति दोबारा नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि शून्यकाल के दौरान सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करवाई जाएगी। शून्यकाल शुरू होने के समय बड़ी

संख्या में विधायक सदन की लॉबी में मौजूद थे। चूंकि विधानसभा अध्यक्ष आसन पर खड़े थे, इसलिए विधायक सदन में प्रवेश नहीं कर सके। स्थिति को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्पीकर से आग्रह किया कि वे कुछ क्षण के लिए बैठ जाएं, ताकि विधायक सदन में प्रवेश कर सकें।

स्पीकर देवनानी ने सहदयता दिखाते हुए कुछ देर के लिए आसन पर बैठकर विधायकों को सदन में आने का अवसर दिया। विधायकों के सदन में प्रवेश के बाद कार्यवाही आगे बढ़ाई गई। इस दौरान स्पीकर वासुदेव देवनानी ने सभी विधायकों से आग्रह किया कि वे कार्यवाही शुरू होने से कम से कम पांच मिनट पहले सदन में पहुंचें, ताकि सदन के समय का सही उपयोग हो सके।

‘नेता प्रतिपक्ष के बयान में न सकारात्मकता, न विकास की सोच’

- अविनाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सदन में विपक्ष की बोलाती बंद कर दी है
- बालमुकुंद आचार्य ने 5 साल बनाम 2 साल के कार्यकाल की तुलना करते हुए कहा कि विपक्ष को राजनीति करनी चाहिए, जनता के साथ मज़ाक नहीं

ने नेता प्रतिपक्ष के वक्तव्य को निरर्थक करार दिया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के भाषण में न तो कोई सकारात्मक दृष्टिकोण था और न ही विकासोन्मुख सोच दिखाई दी। बेदम ने कहा कि 40 मिनट के भाषण में नेता प्रतिपक्ष ने केवल राहुल गांधी का उल्लेख किया और नेहरू परिवार की चापलूसी करते रहे।

अविनाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सदन में विपक्ष की बोलाती बंद कर दी है। अविनाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल की तुलना पिछली सरकार के 5 वर्षों के कामकाज से करते हुए विपक्षित रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं

को आंकड़ों और तथ्यों के साथ बहस की खुली चुनौती दी और कहा कि अगर हिम्मत हो तो बहस करिए, आज सच में मज़ा आ गया जब मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष को जवाब दिया।

विधानसभा परिसर में मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक गुरवीर सिंह बराड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने महज 2 वर्षों में जो विकास कार्य किए हैं, उससे कांग्रेस पूरी तरह बोखला गई है। उन्होंने कहा कि इसी का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री ने सदन में 143 बिंदुओं का विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत कर कांग्रेस के 5 साल बनाम भाजपा सरकार के 2 साल के कार्यों की तुलना रखी।

‘2030 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय सौर ऊर्जा की क्षमता का लक्ष्य’

जयपुर । राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा की अनुमानित क्षमता 828 गीगावाट है, जबकि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई) के अनुसार राज्य में 150 मीटर ऊँचाई पर पवन ऊर्जा की अनुमानित क्षमता 284 गीगावाट है। यह आंकड़े साबित करते हैं कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा केंद्र बनने की क्षमता रखता है। राठौड़ के सवाल के जवाब में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाईक ने सदन को यह जानकारी दी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि केंद्र सरकार की सोलर पार्क एवं अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना योजना के अंतर्गत राजस्थान में सोलर पार्क स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से भादला, फलोदी-पोकरण, फतेहगढ़, नोख, पुगल बीकानेर एवं

- केंद्र सरकार की सोलर पार्क एवं अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना योजना के तहत राजस्थान में 10,726 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क स्वीकृत : मदन राठौड़

जैसलमेर क्षेत्र शामिल है। राज्यसभा सांसद राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर प्पुन बिजली योजना के तहत राजस्थान में अब तक 1,31,057 घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित हो चुके हैं। इससे आम जनता को बिजली बिल से राहत मिल रही है और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि रोजगार के विषय में पीएलआई योजना के तहत देशभर में अब तक लगभग 13,600 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं, जिनमें से 3,156 रोजगार जयपुर तथा 20 रोजगार बाड़मेर जिले में सृजित हुए हैं।

मदन राठौड़ द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के विस्तार को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उडके ने बताया कि केंद्र सरकार जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, खेल एवं कौशल

विकास को सशक्त बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। दिसंबर 2025 तक देशभर में कुल 723 ईएमआरएस स्वीकृत किए जा चुके हैं।

राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देशभर में 42 ईएमआरएस का उद्घाटन किया गया, जिनमें आंध्र प्रदेश में 2 और तेलंगाना में 4 विद्यालय शामिल हैं। इसके साथ ही 50 ईएमआरएस की आधारशिला रखी गई। राजस्थान में इस अवसर पर 3 ईएमआरएस का उद्घाटन किया गया। उन्होंने बताया कि ईएमआरएस में शिक्षा एवं खेल सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आधुनिक कक्षाएं, विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल मैदान, खेल उपकरण, स्मार्ट बस, इंटरनेट सुविधा, संगीत व कला कक्ष, तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही है।

विशेष दिव्यांगों को गति देने के लिए निशुल्क अंगदान शिविर आयोजित



शिविर में बी एम वी एस एस संस्था के विशेषज्ञों ने कृत्रिम अंगों को बनाने की पूरी विधि के बारे में जानकारी दी।

जयपुर। सेवा और करुणा की गहरी भावना के साथ, उत्तरी भारत की क्षेत्रीय ग्रैंड लॉज के तत्वावधान में प्रोजेक्ट डिनिटी तथा प्रोमेसस सोसायटी, जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में एक महत्वपूर्ण अंगदान (लिव्ब डोनेशन) शिविर का आयोजन किया श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति में किया गया।

शिविर 3 फरवरी को प्रारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन रीजनल ग्रैंड मास्टर राइट वर्षिपफुल ब्रदर पुनीत सोहल तथा जयपुर की तीनों लॉज के वर्तमान वर्षिपफुल मास्टर ब्रदर अमरदीप सिंह, ब्रदर समीर भार्गव और ब्रदर पुष्पेंद्र सिंह राष्ट्रवर ने दीप प्रज्वलन कर किया।

मामले की जांच में इतना समय लगेगा तो कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार : हाईकोर्ट

जयपुर। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में हुए करोड़ों रुपये के घोटालों की जांच नहीं करने से जुड़े मामले में अदालती आदेश की पालना में एसीबी के डीआईजी व मामले में गठित की गई एसआईटी के मुखिया आनंद शर्मा अदालत में पेश हुए। अदालत ने उन्हें कहा कि एसीबी जांच में इतना समय लगाएगी तो भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि एक प्रतिशत भ्रष्टाचार पर भी कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है, जो एक चिंतनीय विषय है। अदालत ने एसीबी को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता की दी गई शिकायतों पर तुरंत प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट दर्ज करें। इसके साथ ही डीआईजी से दो सप्ताह में जांच पूरी कर 23 फरवरी तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह आदेश टीएन शर्मा की याचिका पर दिए।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पीसी भंडारी ने कहा कि अदालत ने 6 सितंबर 2024 को टेडरों की जांच के लिए अदालत से समय मांगा। इस पर अदालत ने एसआईटी के मुखिया को दो सप्ताह में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

- घोटालों की जांच नहीं करने से जुड़े मामले में आदेश की पालना में एसीबी के डीआईजी व मामले में गठित की गई एसआईटी के मुखिया आनंद शर्मा अदालत में पेश हुए अदालत ने उन्हें कहा कि एसीबी जांच में इतना समय लगाएगी तो भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा

कोई जांच नहीं की। जबकि वह लगातार पूरे तथ्यों के साथ एसीबी में मामले पेश करता रहा है। इनमें से केवल एक मामले में एसीबी ने 27 अक्टूबर 2025 को एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में भी चार महीने बाद ही एसीबी ने शिकायतकर्ता के बयान तक दर्ज नहीं किए हैं। वहीं एसीबी ने मामलों की जांच के लिए अदालत से समय मांगा। इस पर अदालत ने एसआईटी के मुखिया को दो सप्ताह में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

काम कम, ब्रांडिंग ज्यादा; मुख्यमंत्री रील बनाने में व्यस्त : टीकाराम जूली

जयपुर। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार की कार्यशैली, प्रशासनिक स्थिति और नीतियों को लेकर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार में ज़मीनी काम भले ही न हो, लेकिन ब्रांडिंग पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

जूली ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रील बनाने में व्यस्त हैं और केवल ब्रांडिंग के लिए आठ करोड़ रुपये का ठेका दे रहा है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि सरकार ने कई यूथयूथ चैनल बना रखे हैं, जिन पर सौ लोग भी दर्शक नहीं होते।

जूली ने प्रशासनिक हालात पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के जाने के बाद यह चर्चा होने लगी कि अब अगला नंबर किसका है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि हमें लगा नहीं है कि सरकार के पास 10,726 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से भादला, फलोदी-पोकरण, फतेहगढ़, नोख, पुगल बीकानेर एवं

- अभिभाषण पर बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार की कार्यशैली, प्रशासनिक स्थिति और नीतियों को लेकर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार में ज़मीनी काम भले ही न हो, लेकिन ब्रांडिंग पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं

- नेता प्रतिपक्ष जूली ने विदेश नीति को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर रहा है

सुनते, मंत्री कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनकी कोई नहीं सुन रहा। इस बयान पर संसदीय कार्य मंत्री ने आपत्ति जताई, जिससे सदन में कुछ देर नोकझोंक भी हुई।

जूली ने कहा कि सरकार के मंत्रियों के कारण कई जगह विधायकों को गांवों में जाने तक में दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायकों पर दादागिरी के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं जनप्रतिनिधियों को धरने की धमकी देनी पड़ रही है,

तो कहीं अधिकारियों द्वारा नए और गरीब जनप्रतिनिधियों का मजाक उड़ाया जा रहा है।

नेता प्रतिपक्ष ने विदेश नीति को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि यह कैसी विदेश नीति है।

जूली ने अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने का भी जिक्र किया और

कहा कि जो टैरिफ पहले शून्य था, वह अब 18 प्रतिशत कर दिया गया है। जूली ने आरएसएस और वंदे मातरम को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई के समय आरएसएस ने वंदे मातरम और तिरंगे को नहीं अपनाया था। उन्होंने सदन में मौजूद भाजपा विधायकों से सवाल किया कि वंदे मातरम का कौन सा हिस्सा विवादित बताया गया था, लेकिन इस पर कोई विधायक खड़ा नहीं हुआ।

इसके साथ ही जूली ने राइजिंग राजस्थान में हुए 3.5 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार इन समझौतों पर उठ रहे सवालों का जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मालिक नहीं, बल्कि जनता के दूस्ती हैं, इसलिए सवालों के जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है।

जूली ने जेल में सुरंग और जनसुनवाई के दौरान सामने आए जमीन सीढ़ों के मामलों का बवाल देते हुए कहा कि सरकार दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने घर में झांके।

मुख्यमंत्री ने दो वर्ष की उपलब्धियों के दस्तावेज सदन पटल पर रखे

राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए भजनलाल ने कहा, दो वर्ष में राजस्व घाटा 8000 करोड़ कम किया

जयपुर, 5 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुईं बहस का जवाब देते हुए पहली बार दो वर्ष की उपलब्धियों का दस्तावेज सदन के पटल पर रखा। उन्होंने अपने वक्तव्य में सड़क, बिजली, पानी, कृषि, महिला, युवा कल्याण सहित विभिन्न

■ **“खेजड़ी राजस्थान का कल्पवृक्ष, इसे बचाने के लिये कानून लायेंगे।”**

■ **“देश की 11 जनकल्याणकारी योजनाओं में राजस्थान पहले स्थान पर है।”**

■ **“वर्ष 2023 की तुलना में 2025 में 14.13 प्रतिशत अपराध में कमी आई।”**

क्षेत्रों में वर्तमान सरकार द्वारा दो साल में किए गए कार्यों का तुलनात्मक ब्यूरा सदन के सामने रखा और कहा कि राज्य सरकार ने अर्थव्यवस्था को न केवल स्थिरता दी, बल्कि उसे गति और दिशा भी दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेजड़ी राजस्थान का कल्पवृक्ष भी है, राजस्थान की पहचान भी है, जिसकी बढ ते हुए रेगिस्तान को रोकने में हमेशा सार्थक



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब दिया।

भूमिका रही है। शर्मा ने कहा कि हम राज्य के कल्पवृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए कानून भी लाएंगे, जिससे प्रदेश में खेजड़ी संरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने वृक्षारोपण का महाअभियान चलाया और केवल दो वर्षों में 2० करोड़ पौधे लगाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो सालों के कार्यकाल में हमारा प्रदेश 11 जनकल्याणकारी योजनाओं में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। इसी प्रकार 5 राष्ट्रीय योजनाओं में दूसरे स्थान पर और 9 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में तीसरे स्थान के

साथ ही दो प्रमुख आयामों में बेस्ट परफॉर्मर स्टेट का सम्मान हासिल किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को समृद्ध और किसानों को खुशहाल बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। हम पांच साल के भीतर किसान सम्मान निधि को दोगुना करेंगे। दो साल के भीतर ही हम इसे डेढ़ गुना कर चुके हैं।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदमों से वित्त 2 वर्षों से अपराध के ग्राफ में निरन्तर कमी आई है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2025 में

14.13 प्रतिशत अपराधों में कमी दर्ज की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर अत्याचार के मामलों में 28 प्रतिशत तथा महिला अपराधों में 1० प्रतिशत की कमी आई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान तो समय पर कर ही रही है, साथ ही, पूर्ववर्ती सरकार की बकाया पेंशन का भी भुगतान किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र के वादे के अनुरूप हमारी सरकार प्रत्येक वर्ष किए गए नीतिगत निर्णय और विकास के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में लेकर जाएगी।

ईसाई रीति से हुए ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिगु अदालत ने कहा कि विवाह केवल रिश्ते संबंध नहीं, बल्कि एक वैधानिक स्थिति है। जिससे उत्तराधिकार, सामाजिक सुरक्षा और भरण पोषण सहित अन्य परिणाम उत्पन्न होते हैं। जनहित याचिका में अधिवक्ता सुसेन मैथ्यू ने अदालत को बताया कि प्रदेश में ईसाई युगल ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 के तहत विवाह करते हैं। इस अधिनियम के तहत विवाह कराने वाले पादरी की ओर से जो विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसे ही पंजीकृत किया जाने का प्रावधान है। इसके बावजूद इन विवाहों को नगर

निगम के रजिस्ट्रार अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2०09 की गलत तरीके से व्याख्या कर पंजीकृत करने में आनाकानी करते हैं।

याचिका में कहा गया कि विवाह पंजीकरण नहीं होने से ईसाई दंपतियों को पासपोर्ट और वीजा सहित अन्य सरकारी सेवाओं के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे में राज्य सरकार को निर्देश दिए जाए कि वह पादरी को ओर से जारी विवाह प्रमाण पत्रों का पंजीकरण करें।

राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम के प्रावधान ईसाई विवाहों पर लागू नहीं होता है।

संसद में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
प्रधानमंत्री के जवाब के 3समय की प्रतिक्रिया के बारे में विशेष चर्चा हुई।

बैठक में खड़गे के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में द्रमुक के तिरुवि एन. शिवा, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल वर्मा, शिव सेना उद्धव गुट के अरविंद सावंत, आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन ,इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ईटी बशीर अहमद सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया।

बाद में कांग्रेस संसदीय दल के नेताओं की भी पार्टी के सांसद दल के कार्यालय में बैठक हुई जिसमें गांधी सहित पार्टी के कई नेताओं ने हिस्सा लिया।

प.बंगाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
कांग्रेस को एकतरफा समर्थन देना चाहिए। प्रदेश के एक कांग्रेस नेता ने कहा, “यह ठीक है कि आप अपने घर में मजबूत हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरों को कुचल डालों।”

“अकेले चलने के फैसले पर हरी झंडी मिलने की पुष्टि करते हुए, पश्चिम बंगाल से कांग्रेस के एकमात्र सांसद इशा खान चौधरी ने कहा कि इस फैसले को राहुल गांधी का आशीर्वाद प्राप्त है। कांग्रेस बंगाल के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने भी इस फैसले की पुष्टि की।

‘दुनिया का सबसे अमीर देश भी घुसपैठियों को निकाल रहा है’

प्रमंत्री मोदी ने तृणमूल पर निशाना साधते हुए कहा कि तृणमूल घुसपैठियों की वकील बन सुप्रीम कोर्ट तक आ गई है

नयी दिल्ली, 05 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग की मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम और सरकार के आर्थिक सुधारों सहित विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के विरोध पर गुरुवार को राज्य सभा में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की सोच और राजनीति पर तीखे हमले किये। मोदी ने विपक्ष के बहिष्कार के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा का जवाब देते हुए एसआईआर के विरोध के लिए तृणमूल कांग्रेस की आलोचना करते हुए तृणमूल के लोगों को अपने गिरिबां में झांकने की सलाह दी और कहा कि तृणमूल पतन के नये मानदंड बना रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार को निर्मम सरकार बताते हुए कहा कि वह लोगों को भविष्य अंधकार में डाल रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया का सबसे समृद्ध देश भी अपने यहां से गैर कानूनी नागरिकों को निकाल रहा है, लेकिन तृणमूल के लोग घुसपैठियों की

अल-फलाह चेयरमैन सिद्दीकी चार दिन पुलिस हिरासत में

नयी दिल्ली, 05 फरवरी। एक निचली अदालत ने विवादों में घिरे अल-फलाह विश्वविद्यालय के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को कथित धोखाधड़ी और वित्तीय कदाचार के मामले में चार दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

सिद्दीकी को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे आगे की पृष्ठताछ के लिए चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। यह कार्रवाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा दर्ज कराई गई औपचारिक शिकायतों के बाद शुरू की गई है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच) ने उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अपराध शाखा ने यूजीसी की शिकायतों के आधार पर सिद्दीकी के खिलाफ दो अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की थीं।

‘सदन में प्रमंत्री के साथ हादसा हो सकता था, मैंने उन्हें सदन में आने के लिए मना किया था’

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किया बेहद गंभीर चौंकाने वाला खुलासा

नई दिल्ली, 05 फरवरी। संसद के इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ है जब लोकसभा अध्यक्ष ने खुद यह स्वीकार किया है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा और सम्मान को सदन के भीतर ही खतरा था।

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने गुरुार को एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने ही कल (बुधवार) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आने से रोका था। बिड़ला ने आशंका जताई

मेघालय में अवैध कोयला खदान में धमाका, 1 8 मजदूरों की मौत

खदान में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है

■ **प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर गहरा दु:ख जताया, मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रु. व घायलों को 50,०00 रु. देने की घोषणा की।**

ने मोदी के हवाले से एक पोस्टर में कहा, “मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स में हुई दुर्घटना से व्यथित हूं। अपनों को खोने वालों के प्रति मेरी सवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।” मोदी ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख

रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,०00 रुपये दिए जाएंगे।

आधिकारिक रूप से मिली जानकारी के अनुसारमेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में गुरुवार को “अवैध कोयला खदान में विस्फोट होने से कम से कम 16 मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य के फंसे होने की आशंका है। पुलिस महानिदेशक आई नोंगरंग ने यह जानकारी दी। डीजीपी ने बताया कि यह घटना थांगस्कु इलाके में हुई और बचाव दल तलाशी अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा, “हमने अब तक 16 शव बरामद किए हैं, लेकिन विस्फोट के समय खदान के अंदर मौजूद लोगों की संख्या के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है।

‘सदन में प्रमंत्री के साथ हादसा हो सकता था, मैंने उन्हें सदन में आने के लिए मना किया था’

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किया बेहद गंभीर चौंकाने वाला खुलासा

■ **ओम बिड़ला ने कहा उन्हें खुफिया जानकारी के साथ सदन के भीतर के हालात से इनपुट मिला था कांग्रेस के सांसद प्रमंत्री के कुर्सी के पास आकर हंगामा कर तथा अनहोनी करने की योजना बना रहे हैं।**

कि अगर पीएम मोदी कल सदन में आते, तो उनके साथ कोई अप्रत्याशित और अग्रिय घटना घट सकती थी। स्पीकर ने बताया कि उन्हें खुफिया जानकारी और सदन के भीतर के हालात से यह इनपुट मिला था कि

आसाराम के अहमदाबाद आश्रम पर बुलडोजर चलेगा

अहमदाबाद, ०5 फरवरी। आसाराम का अहमदाबाद स्थित आश्रम टूटंगा। गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को मोटेरा आश्रम ट्रस्ट की तरफ से दायर याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में शहर के मोटेरा इलाके में स्थित भूखंड को खाली कराने की सरकारी कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। कोर्ट के फैसले से राज्य सरकार के लिए आश्रम की जमीन अपने कब्जे में लेने का रास्ता साफ हो गया है। आश्रम की 45,०00 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन पर 203० कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाना है। वर्तमान में इस जमीन की मार्केट वैल्यू 5०0 करोड़ रुपए से ज्यादा की है।

गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस वैभवी नानावटी ने इस मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा कि आश्रम में नियमों का उल्लंघन हुआ। उस जमीन का विकास परियोजना को जरूरत भी है, इसलिए सरकार की मांग सही है।

इस फैसले के बाद अहमदाबाद नगर निगम कभी भी आश्रम में बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर सकता है।

राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर पब्लिक प्रॉसीक्यूटर जीएच विर्क ने कोर्ट को बताया कि यह जमीन

■ **गुजरात हाईकोर्ट ने आश्रम की जमीन लेने की सरकारी कार्यवाही को सही ठहराया**

दशकों पहले सीमित धार्मिक उपयोग के लिए दी गई थी। लेकिन, धीरे-धीरे इसका विस्तार होता चला गया।

जबकि, भूमि आवंटन की शर्तों के अनुसार इसका व्यवसायिक उपयोग, अनधिकृत निर्माण और बिना अनुमति विस्तार प्रतिबंधित था। आश्रम परिसर में करीब 32 अवैध स्ट्रक्चर बना लिए गए, जो कानूनी सीमाओं से बाहर है।

उन्होंने बताया कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एएमसी) ने आश्रम को कई बार नोटिस भेजे थे। इसके बाद 21 जनवरी 2०26 को नगर निगम ने आश्रम का आवेदन भी खारिज कर दिया था।

साबरमती नदी किनारे इस आश्रम की स्थापना आसाराम ने 1972 में की थी। आसाराम ने यहां सबसे पहले एक कुटिया बनाई थी, जिसे मोक्ष कुटिया के रूप में पहचाना जाता था। धीरे-धीरे इसी कुटिया के आसपास निर्माण कार्य होता चला गया और बाद में इसे आसाराम मोटेरा आश्रम के नाम से पहचाना जाने लगा।